हरिभूमि

शौर्य भूमि

मंडला | अंजिनया | भुआबिछिया | बम्हनीबंजर | नैनपुर | निवास | बीजाडांडी

जबलपुर, मंगलवार 5 मई 2026

login : www.haribhoomi.com

खबर संक्षेप

लिपिक संघ अध्यक्ष मण्डला हुये सेवानिवृत्त

मण्डला। सतीश कुमार चन्द्रौल कार्यालय परियोजना प्रशासक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना मण्डला अपनी अर्द्ध वार्षिकीय आयु पूर्ण कर शासकीय सेवा 34 वर्ष 10 माह करने के उपरांत दिनांक 30.04.2026 को जनजातीय कार्य विभाग मण्डला से सेवानिवृत्त हुए। जनजातीय कार्य विभाग मण्डला द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई। सतीश कुमार चन्द्रौल शासकीय कर्त्तव्यों के साथ-साथ लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ शाखा मण्डला के अध्यक्ष पद को भी गौरवांवित कर आप अपने कार्यकाल में जो निष्ठा समर्पण और ईमानदारी दिखाई वह सभी कर्मचारियों के लिये प्रेरणादायक है आपका योगदान हमेशा याद किया जायेगा आपके द्वारा किये गये कार्य समाज एवं विभाग के लिए मिशाल है।

खरीफ सीजन के लिए जिले में खाद वितरण शुरू, ई-टोकन प्रणाली लागू

मण्डला। जिले में खरीफ सीजन की तैयारियों के तहत किसानों को खाद वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन द्वारा खाद वितरण को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए ई-टोकन प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से ही किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। जारी जानकारी के अनुसार, प्रथम चरण में यूरिया की 50 प्रतिशत मात्रा के साथ अन्य उर्वरकों की शत-प्रतिशत मात्रा किसानों को दी जा रही है। विभिन्न संयोजनों (कॉम्बिनेशन) में खाद की बुकिंग की जा रही है, जिससे किसान अपनी फसल के अनुसार खाद प्राप्त कर सकें।

अनुकंपा नियुक्ति और पीडीएस पर कलेक्टर के सख्त निर्देश

हितग्राही मूलक योजनाओं में लापरवाही नहीं चलेगी

*** हर शिकायत पर गंभीरता से हो काम।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

जिला योजना भवन में सोमवार को कलेक्टर श्री राहुल नामदेव धोटे की अध्यक्षता में समय-सीमा और विभागीय समन्वय समिति की बैठक हुई। कलेक्टर ने एजेंडावार सभी बिंदुओं की समीक्षा करते हुए दो टूक कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एक भी शिकायत नॉन अटेंड न रहे

कलेक्टर श्री धोटे ने सीएम हेल्पलाइन को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत नॉन अटेंड नहीं जानी चाहिए। 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों में न्यायालय में लंबित प्रकरण, मांग आधारित और अपात्र शिकायतों को नियमानुसार बंद कराएं। सभी विभाग ए ग्रेड रेटिंग में रहना सुनिश्चित करें। निम्न गुणवत्ता के साथ बंद की गई शिकायतों को री-ओपन कराकर हितग्राही की संतुष्टि के साथ क्लोज कराएं। सीएम मॉनिट और सीएस मॉनिट के प्रकरणों में विभाग प्रमुख स्वयं प्रकरणवार पर्सनली फॉलोअप लें।

हर विभाग दे योगदान

जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री धोटे ने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने टास्क समय पर पूरे करने के निर्देश दिए। ईई पीएचई को हैंडपंप, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के पेयजल की लगातार टेस्टिंग करने और अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। एमएसएमई, वन विभाग सहित सभी विभागों से जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने में योगदान देने को कहा गया।

पेयजल व्यवस्था की एसडीएम करेंगे मॉनिटरिंग

पेयजल उपलब्धता की समीक्षा में कलेक्टर श्री धोटे ने कहा कि सिंगल विलेज स्कीम, जल निगम की स्कीम या हैंडपंप, सभी की स्थिति को अनुविभागीय अधिकारी स्वयं मॉनिटर करें। पीएचई की टीम हैंडपंपों की मरम्मत समय पर सुनिश्चित करे ताकि गर्मी में ग्रामीणों को परेशानी न हो।

अनुकंपा नियुक्ति 30 जून तक निराकृत करें

जिला कोषालय अधिकारी के अनुकंपा नियुक्ति पर दिए प्रस्तुतिकरण के बाद कलेक्टर श्री धोटे ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने रोस्टर तैयार करें। लंबित प्रकरणों पर आवश्यक एक्सरसाइज कर एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुकंपा नियुक्ति के सभी लंबित प्रकरण आगामी 30 जून तक अनिवार्य रूप से निराकृत किए जाएं।

फील्ड विजिट जरूरी, निरीक्षण प्रतिवेदन दें

अधिकारियों के फील्ड विजिट और निरीक्षण प्रतिवेदन पर जोर देते हुए कलेक्टर श्री धोटे ने कहा कि सभी जिला अधिकारी दूरस्थ क्षेत्रों का भ्रमण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। फील्ड से मिली वास्तविक स्थिति के आधार पर ही योजनाओं में सुधार होगा।

पीडीएस वितरण शत-प्रतिशत हो

राशन दुकानों के माध्यम से पीडीएस वितरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री धोटे ने जिला आपूर्ति अधिकारी और जिला प्रबंधक नान को आपस में समन्वय बनाकर शत-प्रतिशत राशन वितरण कराने के निर्देश दिए।

अन्य बिंदुओं पर भी दिए निर्देश

बैठक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की प्रगति, वन अधिकार दावों के निराकरण, जर्जर और मरम्मत योग्य स्कूल व आंगनबाड़ी भवनों की जानकारी, शासकीय कार्यक्रमों का प्रोटोकॉल अनुसार आयोजन सहित अन्य अंतर विभागीय बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर श्री धोटे ने सभी बिंदुओं पर समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए।

नियम कानून पर भारी नैनपुर के कब्जाधारी

*** जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिख रहा शासकीय भूमि का अतिक्रमण।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

नैनपुर के नगर विकास में अवैध कब्जाधारियों ने ग्रहण लगा दिया है। यहां नगर क्षेत्र एवं आसपास की जनोपयोगी कीमती शासकीय भूमि में किए गए अवैध कब्जा की खबर पिछले दिनों मीडिया के द्वारा प्रकाशित की गई थी, तब यहां के वार्ड नंबर 7 इटका में 72 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा होना पाया गया था। जिस पर प्रशासन की टीम द्वारा कब्जधारियों को बेदखल करने की कार्यवाही की गई थी। लेकिन अभी भी चकोर नदी स्टापडेम के पास 100 एकड़ शेष शासकीय भूमि का अतिक्रमण जिम्मेदारों को क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही वार्ड नंबर 9 में चिल्ड्रन पार्क एवं अन्य भवन बनाए जाने वाले प्रस्तावित स्थाल पर भी दबंगों का कब्जा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन की कार्यवाही के बाद भी कब्जाधारियों ने अपना कब्जा नहीं छोड़ा है, उक्त 72 एकड़ भूमि पर पुनः कृषि कार्य करने की तैयारी की जा रही है। राजनैतिक संरक्षण के चलते एवं ठोस कार्यवाही के अभाव में कब्जाधारियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। वर्षों से शासकीय भूमि में कब्जा कर फसल उत्पादन करने वाले लोगों से फसल उत्पादन की राशि भी वसूली की जानी चाहिए आखिर कब तक इन कब्जाधारियों से नैनपुर को मुक्ति मिलेगी। क्या जिम्मेदार किसी बड़े आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं। मंचों से अपने भाषण में विकास की बात करने वाले लोग कब तक मौन रहेंगे।

बरगी जलाशय हादसे पर नारायणगंज जनपद ने जताया दुख

नारायणगंज। बरगी जलाशय हादसे में मृत आत्माओं की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया। बताया गया कि बरगी बांध जलाशय में आकस्मिक क्रूज हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना में असमय काल के गाल में समाए व्यक्तियों की स्मृति में जनपद पंचायत नारायणगंज में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में जनपद अध्यक्ष आसाराम भारतीया और उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह एक अपूरणीय क्षति है और पूरा जनपद परिवार दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए जनपद पंचायत के समस्त स्टाफ और पदाधिकारियों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। जनपद पंचायत नारायणगंज के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से अपनी संवेदनाएं प्रेषित कीं। शोक सभा के अंत में भावुक मन से ईश्वर से विनती की गई कि वह मृत आत्माओं को चिर शांति प्रदान करें और प्रभावित परिवारों को इस संकट से उबरने का संबल दें।

कान्हा टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत

*** किसली रेंज के मगरनाला में मिला नर बाघ का शव, आपसी संघर्ष में गई जान।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व की किसली रेंज में सोमवार सुबह एक 4 वर्षीय नर बाघ का शव बरामद हुआ। 'डिगडोला मेल' के नाम से पहचाने जाने वाले इस बाघ का शव मगरनाला क्षेत्र में गश्ती दल को मिला। प्रारंभिक जांच और शरीर पर मिले निशानों के आधार पर वन विभाग ने मौत का कारण दूसरे बाघ के साथ आपसी संघर्ष बताया है।

10 से 12 घंटे पहले मौत का अनुमान

कान्हा टाइगर रिजर्व के उप निदेशक (कोर) प्रकाश कुमार वर्मा ने बताया कि बाघ की मौत लगभग 10 से 12 घंटे पहले हुई होगी। सूचना मिलते ही वन अमला, डॉग स्क्वायड और प्रबंधन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मौत के सटीक कारणों की पुष्टि के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

घायल होने की आशंका पर दूसरे बाघ की तलाश

हाथी गश्ती दल की मदद से क्षेत्र में उस दूसरे बाघ की तलाश की जा रही है, जिससे मृत बाघ का संघर्ष हुआ था। प्रबंधन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लड़ाई में शामिल दूसरा बाघ घायल तो नहीं है। घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम के बाद प्रबंधन विस्तृत रिपोर्ट जारी करेगा।

अप्रैल माह में 6 बाघों की मौत

कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अप्रैल माह में ही दो बाघिनों और चार शावकों की जान जा चुकी है। इसमें 5 अप्रैल को बाघिन सुनैना और 29 अप्रैल को बाघिन टी-141 व उसके अंतिम शावक की मौत शामिल है। वर्तमान घटना के बाद पार्क प्रबंधन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

भाजपा ने मनाया जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं को बांटी झालमुरी

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक-दूसरे को बधाई दी और पार्टी की जीत का उत्सव मनाया। जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को झालमुरी वितरित की और मिठाई खिलाकर सभी का मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत देश की जनता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पार्टी की नीतियों पर अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा विकास, सुशासन और जनसेवा को प्राथमिकता दी है, जिसका फल आज पूरे देश में देखने को मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण और जनता के आशीर्वाद से पार्टी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। यह जीत केवल एक राज्य की जीत नहीं, बल्कि पूरे देश में भाजपा के बढ़ते जनाधार और विश्वास का प्रतीक है। इस अवसर पर देवसिंह सैयाम, जयदत्त झा, जोरावर सिंह, थामन बरमैया, रोचीराम गुरवानी, सुरेंद्र दुबे, पारस असरानी, विनय मिश्रा, सुधीर दुबे, नरेश कछवाहा, अनुराग बिटटू चौरसिया, बसंत चौधरी, संजय गुप्ता, सुधीर मिश्रा, सुनील मिश्रा नितिन राय, सचिन शर्मा, सौरभ गुप्ता, अंकित ज्योतिषी, शानू दुबे, श्याम दुबे, शेखर निखारे, सावन नीखर, रवि सोनवानी, मोंटी मलिक, उत्कर्ष यादव, अमित शर्मा, ऋषभ सिन्हा, देव रजानी, पंकज दुबे, संतोष कछवाहा, नीरज कांड्रा, जहूर मोहम्मद, आशीष चौरसिया, रमेश पंजवानी, श्री अग्रवाल, कपिल सचान, ब्रजेश गोमास्ता, आनंद जैन, ओमप्रकाश धामेची, सुनील जंघेला सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गृह प्रवेश | मंत्री संपतिया उईके ने कराया गृह प्रवेश।

विस्थापित परिवारों का पुनर्वास हुआ शुरू

*** चुटका परमाणु परियोजना के हैं विस्थापित।**

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

चुटका परमाणु परियोजना के अंतर्गत ग्राम चुटका से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुनर्वास सोमवार से प्रारंभ हो गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उईके ने आर एंड आर कॉलोनी गौंझी में नए घरों में शिफ्ट होने वाले परिवारों का शुभ गृह प्रवेश कराया। इस अवसर पर उन्होंने परिवार के मुखिया को अवार्ड राशि का प्रतीक चेक भी सौंपा और सभी परिवारों को नए घर में प्रवेश की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

एनपीसीआईएल की चुटका परमाणु परियोजना के लिए ग्राम चुटका के 330 परिवार विस्थापित हो रहे हैं। इन सभी परिवारों का पुनर्वास आर एंड आर कॉलोनी गौंझीमाल में किया जाएगा। कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने फोन कर नव प्रवेशी परिवारों से आत्मीय बातचीत की और नये घरों में प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी परिवारों को शासन की ओर से हरसंभव सहायता के लिए आश्वस्त किया।

कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे ने सोमवार को गृह प्रवेश करने वाले 27 परिवारों से बातचीत कर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आगामी एक माह तक नव प्रवेशी परिवारों के व्यवस्थित होने तक भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। कलेक्टर श्री धोटे ने एसडीएम मंडला को निर्देश दिए कि सभी परिवारों को आवश्यकता अनुसार गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएं।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद कछवाहा, जनपद पंचायत अध्यक्ष संतोष सोनू भलावी सहित अन्य जन प्रतिनिधि, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, एसडीएम मंडला श्रीमती सोनल सिडाम व एनपीसीआईएल के अधिकारी मौजूद रहे। ईई पीएचई मनोज भास्कर, एसी ट्राइबल श्रीमती वंदना गुप्ता, तहसीलदार हिमांशु भलावी, सहायक संचालक जनजातीय कार्य श्री रंजीत गुप्ता, डीपीएम आजीविका मिशन भगवानदास भैंसारे, जिला प्रबंधक नीलेश दुबे व श्रीमती ममता अर्सिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।

बच्चियों को बचाते हुए आरक्षक की डूबने से मौत, देवगांव संगम में हुआ हादसा

हरिभूमि न्यूज ⏭ मण्डला

मंडला जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र में सोमवार को एक पुलिस आरक्षक शिवलाल परस्ते की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा देवगांव स्थित नर्मदा और बुडनेर नदी के संगम पर हुआ, जहां आरक्षक अपने परिवार के साथ स्नान करने गए थे। अपनी बच्चियों को बचाने के प्रयास में वे गहरे पानी में डूब गए, हालांकि उनकी बच्चियों को सुरक्षित बचा लिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरक्षक शिवलाल परस्ते पिछले लगभग 11 महीनों से मोहगांव थाने में पदस्थ थे। उनकी पत्नी बिछिया क्षेत्र में शिक्षिका हैं और बच्चे भी अपनी मां के साथ वहीं रहते थे। छुट्टियों के कारण पत्नी और बच्चे मोहगांव आए हुए थे। सोमवार को परिवार देवगांव संगम पर घूमने और स्नान करने गया था।

बताया गया कि स्नान करते समय उनका बेटा अचानक गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए उनकी दो बेटियां भी पानी में उतरीं, लेकिन वे भी डूबने लगीं। यह देख आरक्षक शिवलाल तुरंत पानी में कूद पड़े। उन्होंने और वहां मौजूद अन्य लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इसी दौरान शिवलाल खुद गहरे पानी में डूब गए।

न्यायालय तहसीलदार मण्डला, जिला मण्डला

आम सूचना-पत्र

कमांक/प्रवा तह./ मण्डला, दिनांक 24.04.2026

किशोर कुमार श्रीवात्री पिता श्री चोखेलाल श्रीवात्री निवासी पीपरपानी तहसील मण्डला जिला मण्डला

आवेदक / वसीयतग्रहिता...

विरूद्ध

अहिल्या श्रीवात्री पति दादूलाल श्रीवात्री निवासी पीपरपानी तहसील व जिला मण्डला

अनावेदक / वसीयतकर्ता....

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पीपरपानी प.ह.नं. 62 रा.नि.मं. महाराजपुर स्थित ख.नं. 560/1 रकवा 0.32 हे. भूमि. जो राजस्व अभिलेखों में के नाम पर दर्ज है यह कि भूमि स्वामी की दिनांक 17.11.2025 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक भूमिस्वामी द्वारा निष्पादित/ नोटराईज्ड वसीयतनामा दिनांक 03.02.2023 के आधार पर वसीयतग्रहिता किशोर कुमार श्रीवात्री पिता श्री चोखेलाल श्रीवात्री निवासी पीपरपानी द्वारा नामांतरण कराये जाने हेतु म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो इस न्यायालय में गतिशील है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियत पेशी दिनांक 13.05.2026 को प्रातः 11.00 बजे तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा/आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावे / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

तहसीलदार मण्डला

खबर संक्षेप

रास्ता रोककर की मारपीट

चीचली। स्थानीय पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस ग्राम घघरौला निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि मैं अपने मित्र हेमराज रजक के साथ ग्राम तेंदुखेडा से घघरौला आ रहे थें। रास्ते में तालाब के पास गांव का रानू यादव मिला और पुरानी बुराई को लेकर रास्ता रोकते हुये गंदी गंदी गालिया देने लगा। जब प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना किया तो रानू द्वारा लाठी से मारपीट करते हुये चोटे पहुंचाई। इसी दौरान रानू का भाई बाबू लाल यादव भी आ गया उसने भी मारपीट की गई। घटना को देखते हुये प्रार्थी के साथी द्वारा जब बीच बचाव करने का प्रयास किया गया तो उसके साथ भी मारपीट करते हुये चोटे पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

पति पत्नी के साथ की मारपीट

गाडरवारा। समीपस्थ डोगरगांव पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस ग्राम पटकुही निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि मेरे घर के बाजू में संतोष ठाकुर रहता है जो आये दिन शराब पीकर गाली गलौच करते रहता है। इसी बात को लेकर इससे बुराई चल रही है। बीते हुये दिवस जब प्रार्थी अपने गांव की ओर जा रहा था तो रास्ते में संतोष ठाकुर शराब के नशे में गाली दे रहा था। जब प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना किया और उसी समय संतोष का साला पूरन ठाकुर व संदीप ठाकुर भी आ गये। इसके बाद तीनों ने एक राय होकर गाली देते हुये लाठी से मारपीट कर चोटे पहुंचाई। वही घटना को देखकर जब प्रार्थी की पत्नी बच बचाव करने के लिये आई तो उसके साथ भी मारपीट करते हुये चोटे पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

रोड से पानी निकलने की बात पर हुआ विवाद

कल्याणपुर। डोगरगांव पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस ग्राम इमालिया निवासी एक व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि मेरा घर ग्राम इमलिया में नेतराज कौरव के घर के सामने है। मेरे घर का पानी रोड से निकलता है तथा मेरे घर के बाजू में कचडा फेकने का घूरा बना है जिसमे मेरे घर का कचडा एवं गोबर डालते है। इसी बात को लेकर नेतराज कौरव और उसका लड़का साकेत कौरव एवं रानू उर्फ शशि कान्त कौरव कहते है कि यहाँ पर पर कचरा एवं गोबर मत डाला करो। इसी बात को लेकर बीते हुये दिवस नेतराज कौरव एवं उसके लडके साकेत कौरव एवं रानू उर्फ शशि कान्त कौरव गोबर की बात को लेकर गंदी गंदी गालिया देते हुये लाठी से मारपीट करते हुये चोटे पहुंचाई। वही बीच बचाव करने के लिये जब प्रार्थी की पत्नी आई तो उसके साथ भी गाली देते हुये जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर आरोपियों के खलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

महिला को दी गई जान से मारने की धमकी

गाडरवारा। समीपस्थ डोगरगांव पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस ग्राम कल्याणपुर निवासी एक महिला द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि जब वह अपने घर पर अकेली थी उसी समय गांव को हेमराज कुशवाहा आया और गंदी गंदी गालिया देते हुये जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर प्रार्थिया द्वारा की गई पुलिस थाने में शिकायत पर पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

पंचर बनाने वाले को ईट पत्थर से मारा

गाडरवारा। समीपस्थ सांईखेड़ा पुलिस थाने से मिली जानकारी के अनुसार बीते हुये दिवस ग्राम रम्पुरा निवासी एक पंचर दुकान चलाने वाले व्यक्ति द्वारा पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हुये बताया है कि जबव वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था उसी समय गांव को सुरेश पटैल आया और गंदी गंदी गालिया देने लगा। जब प्रार्थी द्वारा गाली देने से मना किया तो आरोपी द्वारा ईट पत्थर मारते हुये चोटे पहुंचाई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना को लेकर प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला कायम करते हुये जांच में लिया गया है।

प्रशासन की अनदेखी खड़ा कर रही सबाल...?

शासकीय चिकित्सालय क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से मरीजों सहित आमजन की जिन्दगी खतरे में

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। नगर ही नही बल्कि गाडरवारा तहसील की सबसे बड़ा शासकीय चिकित्सालय अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझते हुये देखा जा रहा है। जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो चिकित्सालय क्षेत्र में जिस प्रकार से अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है उसके चलते यहां पर भर्ती रहने वाले मरीजों के साथ साथ चिकित्सालय को आने जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा चिंता जनक स्थिति में दिखाई देने से नही चूक पा रही है..? बताया जाता है कि यहां पर भर्ती रहने वाले मरीज जहां अपने आपकों को असुरक्षित महसूस करते हुये देखे जा रहे है तो कुछ इसी प्रकार का हाल चिकित्सालय में आने जाने वाली आम महिलाओं का भी देखने मिल रहा है.? क्योंकि शासकीय चिकित्सालय परिसर के ठीक सामने यानि की मुख्य मार्ग पर जिस तरह अतिक्रमण हो रहा है उसके चलते चिकित्सालय की सुरक्षा को तो ग्रहण लग ही रहा है साथ ही साथ यातायात व्यवस्था में भी बाधा पहुंचने से नही चूक पा रही है। चिकित्सालय के सामने मुख्य मार्ग के किनारे पड़ी हुई शासकीय भूमि पर लोगो द्वारा लगातार अतिक्रमण करते हुये जिस तरह से दुकाने स्थापित की जा रही है उसके चलते आमजन के लिये खतरा पैदा हो रहा है..। मगर इसके बाद भी प्रशासन द्वारा इस सच्चाई को लेकर जिस प्रकार से चुप्पी साधी जा रही है उसके चलते यहां की चिंता जनक स्थिति बनने से नही चूक रही है। यह बात अलग है कि बीते हुये वर्ष प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को हटाते हुये तार बाडी कर दी गई थी। मगर अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने उस तारबाडी को तोडकर अपनी दुकान फिर सजाने में कोई कसर नही छोडी गई है। नगर के शासकीय चिकित्सालय के चारों ओर फैल रहे अतिक्रमण के चलते यह हाल बन चुका है कि मरीजों का चिकित्सालय के अंदर प्रवेश कर पाना मुश्किल होने लगा है। चिकित्सालय के गेटों से सट लगी हुई दुकानों के चलते जब कोई मरीज बाहर आ रहा होता है तो मुख्य मार्ग से निकलने वाले वाहन दिखाई नही देते है जब तक वह उन वाहनों को देख पाता है दुर्घटना घटित होने से नही बच पाती है। इस यह अतिक्रमण दुर्घटनाओं का कारण तो बन ही रहा है। वही दूसरी ओर यहां पर स्थापित की गई दुकानों पर आवारा गर्दी करने वालों का जमावडा लगा रहना आम बात बन चुकी है। मगर प्रशासन की अनदेखी का परिणाम है कि देर रात तक यहां पर मनचलों का जमावड़ा लगा रहने की स्थिति में चिकित्सालय में भर्ती रहने वाली महिला मरीजों सहित अन्य मरीज अपने आपको पूर्णरूप से असुरक्षित महसूस करने के साथ साथ दहशत में दिखाई देने लगे है? सच्चाई पर यदि गौर किया जावे तो अतिक्रमण कारियों को प्रभावशाली लोगों के साथ साथ जिस तरह से प्रशासन का पूरा संरक्षण प्राप्त होने की सच्चाई इस बात से उजागर होते हुये जान पड़ रही है कि अतिक्रमणकारियों को जिस प्रकार से बिजली व नल कनेक्शन मिल रहे है वह निश्चित नियम के विपरित माने जाते है..? जबकि नियम के अनुसार देखा जावे तो यदि किसी आम नागरिक को नपा से नल कनेक्शन व बिजली विभाग से कनेक्शन लेना होता है तो अनेक प्रकार से उसे अपने आवास या जमीन संबंधी दस्तावेज पेश करना पड़ते है और इसी के बाद बिजली तथा नल कनेक्शन मिल पाता है। मगर यहां पर अतिक्रमण कारियों की दुकानों से लेकर टपरों में बिजली मीटर सहित नल लगे हुये देखे जा रहे है। वह निश्चित ही इस बात की सच्चाई उजागर करने से नही चूक पा रही है कि नपा व बिजली विभाग द्वारा सभी निमयों को दर किनार करते हुये इन्हे कनेक्शन देने में कोई कसर नही छोड़ी गई होगी..? यदि इन विभागों द्वारा अतिक्रमण कारियों को इन जरूरी सुविधाओं से बंचित रखा जाता तो निश्चित तौर से अधिक्रमण पर काफी हद तक अंकुश लग सकता था। मगर शासकीय संस्थाओं द्वारा अतिक्रमणकारियों को जरूरी सुविधाओं के लिये सहूलियत प्रदान की जा रही है उससे यह विभाग भी अतिक्रमण करने वालों के लिये संरक्षण की मुद्रा में दिखाई देने से नही चूक रहे है..? क्योंकि शासकीय चिकित्सालय के सामना वाला मार्ग नगर का प्रमुख मार्ग माना जाता है। इस मार्ग से दिन भर जहां स्कूली छात्र छात्राओं का आना जाना लगा रहता है।

अप डाउन संस्कृति पर नहीं लग पा रही रोक, शासन की योजनाएं हो रही फेल...

मनमर्जी के मुताबिक संचालित होते है शासकीय कार्यालय...?

हरिभूमि न्यूज/सांईखेड़ा। जहां एक ओर प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाकर आमजन तक पहुंचाने के लिए शासकीय विभाग बनाये गये है और इन शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग से ही लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। मगर देखा जा रहा है कि पुलिस से लेकर अन्य शासकीय कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों की उदासीनता कही जावे या फिर उप डाऊन करने की प्रवृति में लिप्त मनमानी के चलते शासन की योजनाओं का जहां समय पर लोगों को लाभ नही मिल पाने की स्थिति में समस्त योजनाएं फेल होते हुए जान पड़ने लगी है? जिसमें प्रमुख रूप से देखा जावे तो ब्लाक मुख्यालय के अंतर्गत जितने भी कार्यालय है उनमें चंद अधिकारियों कर्मचारियों को छोड़ दिया जावे तो अनेक अधिकारी ऐसे है जो अप डाउन संस्कृति को न अपनाये हो? यहां के अनेक शासकीय कार्यालायो में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की अप डाऊन संस्कृति के चलते शासन की योजनाए फैल होती जा रही है? यहां पर अनेक विभाग के कार्यालयों में पदस्थ प्रमुख अधिकारियो से लेकर छोटे छोटे कर्मचारी तक अप डाउन कर रहे है? इतना ही नही यहां के प्रमुख ब्लाक कार्यालय व पुलिस थानों के साथ साथ स्कूलों में पदस्थ प्राचार्य सहित तहसील कार्यालय व अन्य विभागों के अधिकारियों सहित अनेक कार्योलयों में का यह हाल चल रहा है? और ऐसा कई सालो से चलता आ रहा है कोई कार्यवाही न होने के कारण अधिकारी अपनी मनमानी से कार्य करते आ रहे है? जब मन करंस आ जाते है जब मन करे तब चले जाते है कोई रोकने वाली नही है...? यह बात जरूर है कि यदि ऐसा कोई छोटा कर्मचारी करे तो नोटिस जारी होने लगते हैर। लेकिन जो उस विभाग का मुखिया होता है उस पर कार्यवाही करने वाला कोई नही रहता? लेकिन आज तक कोई भी जिला स्तर के अधिकारी द्वारा इस अप डाउन संस्कृति के रवैया को अपनाने वाले अधिकारियो पर अंकुश नही लगा पा रहे है? जिसके कारण अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों का खुलने व बंद होने का जो समय निश्चित किया गया है, उस समय पर न तो वह कार्यालय पहुंच पाते है और न ही लोगों की समस्याओं को सुना जाता है? जिसके कारण आम जनता की समस्या का हल नही निकलता व शिकायतें दिनों दिन बढ़ती जाती है? मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक मंगलवार को शुरू किया गया जनसुनवाई कार्यक्रम भी अधिकारियो को याद नही रहता है? जिसके कारण जनसुनवाई भी नही हो पाती है और उस दिन जनता कार्यालयो के पास अपनी समस्या को लेकर मंगलवार के दिन का इंतजार करती है और अपना अपना काम छोड़ कर जनसुनवाई के निश्चित समय 11 बजे के पहले इन कार्यालयो में आ जाते है और साहब के आने का इंतजार करते रहते है? लेकिन जब उन्हें मालूम चलता है कि साहब अभी आये ही नही है इस स्थिति में क्षेत्र के लोगों को निराशा ही हाथ लगती है? अगर कोई उस कार्यालय में मौके पर उपस्थित किसी चपरासी से पूछे तो वह भी यही कह देता है कि जनसुनवाई का कोई औचित्य नही रह गया है? साहब को सप्ताह के अन्य दिन वैसे ही मंगलवार का रहता है, साहब उसी समय पर आयेगे जिस समय ट्रेन आएगी, साहब भी बेचारे क्या करे वह तो आना चाहते है पर ट्रेन लेट हो जाती है जिस कारण साहब समय पर आफिस नही पहुंच पाते है? जब ट्रेन या फिर अन्य वाहन गाडरवारा आयेगाऔर फिर साहब यहां आवेगे? जिससे कार्य प्रभावित होते है तो होते रहे अब अपने परिवार थोड़ी छोड़ देवे? यह हाल एक ही कार्यालय का नही बल्कि ब्लाक व तहसील स्तर से लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भी देखा जा रहा है? क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि यहां के शासकीय कार्यालयों का यही हाल रहा तो क्या शासन की योजनाएं वह जनता की समस्याओं का हल हो पायेगा? अगर शासन प्रशासन को शासन की योजनाओ को जन जन तक लाभ पहुंचना है तो सबसे पहले अप डाउन संस्कृति पर रोक लगाना होगा? अगर इस संस्कृति पर रोक लग गई तो आम जनता के काम वाकई में समय सीमा में होने लगेगे, और आम जनता भी राहत की सांसा लेगी, ऐसी शासन प्रशासन से अपेक्षा है।

राज्य स्तरीय बेडमिंटन में स्वर्ण व कांस्य पदक जीतकर मुदित ने समाज के साथ साथ किया क्षेत्र का नाम रोशन

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। खेल हो या फिर अन्य किसी प्रकार की सफलता जब क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे शहरों में पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ सफलता हासिल करता है तो निश्चित तौर से सम्पूर्ण क्षेत्रवासियों के लिये गौरव की बात बनने से नही चूक पाती है। कुछ इसी प्रकार से बीते हुये दिनों 12वीं राज्य स्तरीय स्कूल शिक्षा विभाग अधिकारी कर्मचारी बैडमिंटन प्रतियोगिता जो 1 मई से 3 मई तक डबल्स छतरपुर में आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में शासकीय राघव कृषि उ मा विद्यालय बोहानी के प्रयोग शाला में पदस्थ शिक्षक मुदित कौरव ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन करते हुये प्रथम स्थान के साथ स्वर्ण पदक एवं सिंगल्स में कांस्य पदक जीतकर अपने साथ साथ संपूर्ण क्षेत्र व अपनी कौरव समाज का नाम रोशन किया गया है। ज्ञात हो कि इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के समस्त संभाग,आदिम जनजाति विभाग,डीपीआई भोपाल की टीमों से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की थी। इस प्रतियोगिता में मुदित कौरव ने 50 वर्ष से कम आयु वर्ग में जबलपुर संभाग टीम की कप्तानी करते हुए कई मैच जीतकर फाइनल में सागर संभाग टीम को पराजित करते हुये यह जीत हासिल की। इसके अलावा सिंगल्स मैच में उन्होंने रीवा संभाग को हराकर काँस्य पदक जीता। मुदि कौरव की इस उपलब्धि पर संयुक्त संचालक अरुण कुमार इंगले, जिला शिक्षा अधिकारी डॉ अनिल कुशवाहा,पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी पी इंदुरख्या, विकासखंड अधिकारी अरविंद वर्मा,संस्था प्राचार्य अजय शर्मा एवं अन्नपूर्णा बैडमिंटन एसोसिएशन के समस्त सदस्यों एवं खिलाड़ियों बधाई देते हुये उज्जबल भविष्य की कामना की गई है।

नवीन विग्रह प्राण प्रतिष्ठा पंच दिवसीय महोत्सव की हुई शुरूआत

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। नगर के श्रीदेव अटल बिहारी मंदिर मे अखिल कोटि ब्रह्माण्ड नायक परमाराध्य लाड़ले ठाकुर श्रीदेव अटल बिहारी लाल के नवीन विग्रह एवं श्रीदेव अटल बिहारी लाल युगल सरकार उत्सव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पंच दिवसीय कार्यक्रम बीते हुये 3 मई से प्रारंभ हो गया है । इस कार्यक्रम के तहत प्रथम दिन दिन रविवार को ब्राह्मण आगमन, मंडल निर्माण एवं रात को भजन संध्या आयोजित हुई। भजन संध्या में श्रवण महाराज एवं उनकी मंडली ने भगवान कृष्ण व राधा जी पर संगीतमय भजन प्रस्तुत किये। आयोजन में सीताराम राठी, कमलेश भार्गव सहित अन्य का सहयोग रहा।

नल जल योजना के नाम पर शहरों के साथ साथ गांवों में खोदी जा रही सड़कों से आमजन हो रहे परेशान

हरिभूमि न्यूज/चीचली। शहरों से लेकर गांव गांव नल जल योजना के तहत नर्मदा जल व शुद्व पेयजल प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा लगातार पैसा तो खर्च किया जा रहा है। मगर इस बात की कोई उम्मीद नही है कि नर्मदा जल कब आ पायेगा और आ पाता है कि नही इस बात की भी कोई गारंटी नही है..? मगर इस समय नर्मदा जल लाने के लिये जिस तरह से शहरों के साथ साथ गांवों में लाखों रूपया की लागत से बनी हुई सड़को की खुदाई की जा रही है उसके चलते सड़को सूरत बदहाल होने से नही चूक पा रही है? बताया जाता है कि जल सप्लाई करने के लिये निर्माण करने आई हुई कंपनी द्वारा जिस तरह से मजबूज सड़को के बीचों बीच से खुदाई करते हुये उन्हें तहस नहस कर दिया गया है उसके चलते लोगों के वाहन निकलने की बात तो दूर पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह शहर के सड़को की खुदाई करते हुये उन्हें बदहाल बनाये जाने के कारण जहां नगर के व्यापारियों का धंधा प्रभावित होने से नही चूक पा रहा है तो दूसरी ओर लोगों को अपने घरों तक वाहन ले जाना भी मुश्किल हो रहा है? वही दूसरी ओर इस प्रकार से सड़को की खुदाई किये जाने के चलते नगर पालिका प्रशासन के साथ साथ पंचायतों को भी लाखों की क्षति का सामना करने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। मगर जब भी इस तरह इस योजना को लेकर चर्चा की जाती है तो सिर्फ जिम्मेदारों के मुंह से एक ही बात सुनने मिलती है कि इस योजना का आदेश तो ऊपर से ही आया है इसमें हम क्या कर सकते है। जबकि सच्चाई पर गौर किया जावे तो योजना के नाम पर किये जाने वाले कार्य को पूर्ण करने के लिये आये हुये एजेन्सी द्वारा न तो योजना से संबंधित कोई वोर्ड स्थापित किया जाता रहा है और न ही निर्माण के संबंध में किस गुणवत्ता के साथ काम करने के नियम है उस सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है..? जिसके चलते जहां निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सी पूर्णरूप से मनमाना पूर्ण रवैया अपनाते हुये लाखों की लागत से बनी हुई सड़को को छल्लनी करने में कोई कसर नही छोड़ रही है। जबकि नियम के अनुसार तो यह बताया जाता है कि शहर के अंदर इस योजना के तहत विछाई जाने वाली पाईप लाईन के लिये सड़क के किनारे मजदूरों के माध्यम से खुदाई कराई जावेगी, जिससे सड़को को छति न पहुंचे और आसपास रहने वाले लोगों को भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करने के लिये मजबूर न होना पड़े? मगर यहां पर धडल्ले से मशीनों के माध्यम से सड़को के बीचों बीच खुदाई करते हुये देखा जा रहा है जो वर्तमान समय में यह योजना आमजन के लिये परेशानी का कारण साबित होने से नही चूक पा रही है तो दूसरी ओर भविष्य में नगरवासियों के लिये परेशानी का कारण साबित होते हुये देखी जावेगी?

कैरोसिन न मिलने से गरीब परेशान, लकड़ी खरीदना भी हो रहा मुश्किल

हरिभूमि न्यूज/गाडरवारा। वर्तमान हाईटेक दौर में हालाँकि शहर के घरों में खाना बनाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है पर शहर की आबादी के बड़े हिस्से में गरीब बर्ग के लोग आज भी कैरोसिन ईधन पर ही निर्भर है जो खाना बनाने के लिए मिट्टी के तेल का ही उपयोग कर रहे है। क्योंकि रसोई गैस के लगातार बढ़ते हुये दामों के बीच और नम्बर लगने में देरी के चलते वह हलाकान होने लगे है। ज्ञातव्य है कि शहर में मिट्टी के तेल की सर्वाधिक खपत होती है, जिसके चलते नगर के गरीबों का कहना है कि विडम्बना की बात है इन दिनों अनेक गरीबों को सरकार की गैस कनेक्शन तो प्रदान किये गये है। मगर उनके भरोसे पूरे घर का खाना बन सके यह संभव नही है। क्योंकि गैस के लगातार बढ़ रहे दामों के बीच गरीब परिवारों के लिये गैस खरीदना मुश्किल होने लगा है। इस स्थिति में जिन लोगों को शासन द्वारा गैस कनेक्शन प्रदान किये गये है उन्हें मिट्टी तेल देना बंद कर लिया गया है और जलाऊ लकड़ी के चल रहे भाव आस मान को छूते हुए दिखाई दे रहे है जो गरीबों द्वारा खरीद पाना मुश्किल जान पड रहा है तथा नगर में कैरोसिन की भी किल्लत है। क्योंकि अनेक गरीबों को शासकीय दुकानों से मिट्टी का तेल नही मिल पा रहा है। इस प्रकार से नागरिक खाद्य आपूर्ति विभाग की कैरोसिन के वितरण में कोताही बरतने का नतीजा है कि गरीबों को जरूरत के हिसाब से मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है? उन्होंने बताया कि सहकारी दुकानों से गरीबो को जहां कैरोसीन नही दिया जा रहा है वह कुछ गरीबों को मात्र चंद लीटर कैरोसिन हर माह वितरित किया जाने लगा है और शहर में अब मिट्टी के तेल की कालाबाजारी भी होने लगी है। शहर के अनेक गरीबो का आरोप है कि वास्ताविक हितग्राही तो मिट्टी के तेल से वंचित है। मगर विडम्बना की बात है कि होटलो, मिठाई की दुकानो के संचालक ब्लेक में कैरोसिन खरीद गरीबो का ऱ्इंधन माने जाने वाला मिट्टी का तेल अपनी भट्टियो में फूंक रहे है। शहर के मजदूरो, गरीब परिवारो की गृहणियो ने प्रशासन से मॉग की है कि शहर में मिट्टी के तेल की हो रही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने की पहल करें ताकि गरीब अपने घरों में आसानी से दो वक्त चूल्हा जला सके।

ग्रामीण क्षेत्रो में निर्धारित समय पर खोली जाए उचित मूल्य की दुकानें

हरिभूमि न्यूज/ गाडरवारा। शासन द्वारा गरीबों के हितों का ध्यान रखते हुए उन्हें सस्ता राशन उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित सस्ते राशन की दुकानों से हालाँकि सरकार की मंशानुरूप गेहू, कैरोसिन, चॉवल और शक्कर का वितरण किया जा रहा है। वही सरकार के आदेश अनुसार कुछ महिनों तक पर्ची धारकों के लिये निःशुल्क राशन भी वितरण किया जा रहा है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में नीले, पीले कार्डधारियों की शिकायत है कि उचित मूल्य की कई दुकानें ऐसी है जो समय के साथ निश्चत तिथि पर नही खुलने के कारण लोगो का समय व्यर्थ बर्बाद हो रहा है, इस बात की सच्चाई इस समय क्षेत्र के अनेक गांवों में देखने मिल रही है, जहां पर विगत लम्बे समय से लोगों को अनाज नही मिल पाया है? बताया जाता है जिस सहकारी दुकान से चार पांच गांव जुड़े है और विलम्ब से उसके खुलने की स्थिति मे वहॉ उपभोक्ताओं की भीड़ जुट जाती है और महिलाओं को खासकर इन दुकानो से सामान लेने मे परेशान होना पड़ता है? ज्ञातव्य है कि आने वाले और तेज ठंड के मौसम का ध्यान रखते हुए सहकारी दुकानों से गरीबों, अतिगरीबो राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, लिहाजा जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारी दुकाने निर्धारित समय पर खुलें ताकि नागरिको को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

खबर संक्षेप

दो और चार पहिया वाहन आपस में भीड़े

कोतमा। सड़क दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है वहीं वाहन चालकों के द्वारा तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण दुर्घटनाएं घटित हो रही है। रविवार को रात्रि लगभग 9 बजे कोतमा केशवाही रोड में किसान पैट्रोल पंप के पास मोड में दो चार पहिया वाहन आपस में भीड़ गए जिसके कारण दोनों वाहनों को नुकसान हुआ एक वाहन का सामने का बोनट काफी क्षतिग्रस्त हो गया वहीं दूसरे वाहन में भी काफी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि एक चार पहिया वाहन बलबहरा से कोतमा एवं एक चार पहिया वाहन कोतमा की ओर से केशवाही की तरफ जा रही थी दोनों वाहन तेज रफ्तार मे थे और अचानक मोड मे आमने-सामने से टक्कर हो गई जिसके कारण दोनों वाहन के अंदर बैठे लोगो को हल्की चोट लगी जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा मे भर्ती कराया गया घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई।

चंद्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय में हर रविवार लगता है निशुल्क स्वास्थ्य शिविर

अमरकंटक। पवित्र नगरी अमरकंटक में मानव सेवा की अनवरत ज्योति प्रज्वलित करते हुए चंद्राचार्य धर्मार्थ चिकित्सालय में प्रत्येक रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। यह चिकित्सालय श्री कल्याण सेवा आश्रम द्वारा संचालित है, जो विगत लगभग 30 वर्षों से क्षेत्रवासियों के लिए सेवा, समर्पण और करुणा का जीवंत उदाहरण बना हुआ है। रविवार को आयोजित शिविर में कुल 55 मरीजों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) किया गया, जिनका समुचित स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाइयाँ प्रदान की गईं। इस दौरान विशेष रूप से लकवा (पैरालिसिस) एवं मिर्गी रोग से संबंधित जांच एवं परामर्श शिविर भी आयोजित किया गया, जिससे पीड़ित मरीजों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिल सका। शिविर में अपनी सेवाएँ प्रदान करने वालों में डॉ. रजनीश पाण्डेय, डॉ. संतोष कुमार तिवारी, फार्मासिस्ट अभिषेक मिश्रा, लैब टेक्नीशियन राजेश कुमार तिवारी सहित सहयोगी कार्यकर्ता रामस्नेही, सुखनंदन सिंह एवं प्रीतम प्रसाद का सराहनीय योगदान रहा। सभी ने समर्पित भाव से मरीजों की सेवा करते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाया। इस साप्ताहिक स्वास्थ्य शिविर में दूर-दराज से आने वाले मरीजों को न केवल स्वास्थ्य परीक्षण और दवाइयाँ, बल्कि निशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की जाती है, जो इस सेवा को और अधिक मानवीय एवं प्रेरणादायक बनाती है। श्री कल्याण सेवा आश्रम की यह पहल समाज में सेवा भाव को सशक्त करने के साथ-साथ यह संदेश भी देती है कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा है। अमरकंटक की इस पुण्यभूमि पर संचालित यह चिकित्सालय आज भी निरंतर जनकल्याण के पथ पर अग्रसर है।

एम.पी.ई-सेवा - पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के दिए गए निर्देश

उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया कि विभिन्न विभागीय पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को प्रदाय की जा रही सेवाओं को एकीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा एक पोर्टल एवं मोबाईल एप्प (एमपीईसेवा) विकसित किया गया है। पोर्टल पर वर्तमान में 500 से अधिक सेवायें लाईव (संचालित) की जा चुकी हैं एवं शेष अन्य सेवाओं को इस प्लेटफार्म से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। एम.पी.ई-सेवा मोबाईल एप्लीकेशन एन्ड्राइड एवं एप्पल यूजर के लिए क्रमशः गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। उन्होने बताया कि एम.पी.ई-सेवा पोर्टल की समग्र प्रोफाइल के आधार पर शासकीय योजनाओं के पात्रता की जाँच,जिससे नागरिक उपयुक्त शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठा सकते हैं।रियल-टाइम आवेदन ट्रैकिंग एवं स्थिति ज्ञात किए जाने की सुविधा,डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड की सुविधा,इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे सुविधा,सिंगल साइन-ऑन सुविधा उपलब्ध है। उन्होने जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन से कहा है कि आप अपने विभाग के द्वारा प्रदाय की जा रही समस्त प्रकार की सेवायें यदि एम.पी ई-सेवा से जुडी है तो हितग्राहियों/नागरिकों को एम.पी.ई-सेवा -सेवा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करें।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक संपन्न

योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर के सख्त निर्देश

डिंडौरी ।कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई जिसमें जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का जिम्मेदारी से निराकरण करें ताकि हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके। जिन विभागों द्वारा सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं किया गया है उन्हें नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन विभागों में बार बार शिकायतें दर्ज हो रही हैं वहां के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई।

बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और उनके कार्यों की सराहना की गईकलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में संचालित गेहूं उपार्जन केंद्रों से अनाज का शीघ्र उठाव कर सुरक्षित स्थान पर रखा जाए ताकि बारिश के कारण नुकसान न हो । लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। भविष्य में ऐसे केंद्र बनाए जाने के निर्देश दिए गए जहां सामग्री सुरक्षित रखी जा सके और बारिश का पानी न पहुंचे।आबकारी विभाग को अवैध मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विकासखंड स्तर पर जांच करने के निर्देश दिए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए 30 जून तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को आंगनवाड़ी विद्यालय और शासकीय भवनों के साथ अपने घरों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के निर्देश दिए ताकि जल स्तर बना रहे और भविष्य में जल संकट से राहत मिल सके। सभी को जियो टैग फोटो जमा करने के लिए भी कहा गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तिथियां घोषित की गईं जिनमें 7 मई को शहपुरा और 14 मई को अमरपुर में आयोजन किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग से संपर्क करने को कहा गया।बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए 10 मई तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। कृषि विभाग को नरवाई जलाने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग को सड़कों पर चल रही बसों की नियमित जांच कर बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने 25 नए हैंडपंप स्वीकृत

डिंडौरी ।जिले में बढ़ती पेयजल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया के प्रयासों से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न विकासखंडों में नए नलकूप खनन और हैंडपंप स्थापना को स्वीकृति दी गई है।यह स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण के बाद प्रदान की गई। समिति का गठन जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अनुशंसाओं जनसुनवाई और जिला भ्रमण के दौरान मिली मांगों के आधार पर किया गया।

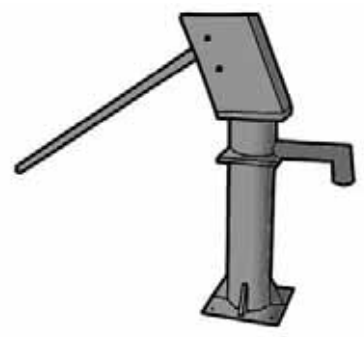

प्रस्तावों के परीक्षण के बाद समनापुर अमरपुर डिंडौरी बजाग शहपुरा मेंहदवानी और करंजिया विकासखंडों की कुल 25 पेयजल प्रभावित बसाहटों में नए हैंडपंप स्थापित किए जाएंगे।लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि इन हैंडपंपों के स्थापित होने से ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा और जल संकट से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्य शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्राथमिकता के साथ पूरे किए जाएंगे।प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि स्वीकृत सभी स्थानों पर जल्द कार्य प्रारंभ किया जाएगा ताकि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े।

डिंडौरी में चाट चौपाटी का शुभारंभ

डिंडौरी। जिला प्रशासन के प्रयासों से सोमवार को गल्ला गोदाम मंडी क्षेत्र में चाट चौपाटी का सुव्यवस्थित रूप से शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथियों द्वारा उद्घाटन के साथ यह पहल उत्साहपूर्ण माहौल में शुरू हुई।कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक ओंकार मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लंबे समय से चली आ रही नागरिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस चौपाटी की शुरुआत की है। यह नगर के सौंदर्यीकरण के साथ नागरिकों और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी।

कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने इस अवसर पर चौपाटी को स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकानों में दो डस्टबिन रखने और प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए ताकि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। चौपाटी का संचालन रात्रि 10 बजे तक सीमित रखने की बात भी कही गई।नगर परिषद को चौपाटी क्षेत्र में शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बैनर और अन्य माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर के मुख्य मार्गों के डिवाइडर पर किसी भी प्रकार के बैनर होर्डिंग या झंडे नहीं लगाने की हिदायत दी गई जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके।

व्यापारियों से अपील की गई कि वे कचरे का उचित निस्तारण करें और स्वच्छता बनाए रखें। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी और प्राप्त राशि से डस्टबिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कार्य में नगर परिषद के साथ पुलिस प्रशासन भी सहयोग करेगा।कांग्रेस विधायक ओंकार मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इस पहल से नगर विकास को नई दिशा मिलेगी और नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न व्यंजनों का आनंद मिलेगा। साथ ही दुकानदारों को नशीले पदार्थों के विक्रय से दूर रहने की सलाह भी दी गई।कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अमला और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

शराब दुकानों में रेट लिस्ट और बारकोड अनिवार्य

डिंडौरी । आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार जिले डिंडौरी की समस्त देशी-विदेशी कम्पोजिट शराब दुकानों में रेट लिस्ट एवं बारकोड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।इस व्यवस्था के लागू होने से आम नागरिक अब शराब दुकानों में उपलब्ध उत्पादों की मात्रा, गुणवत्ता कीमत एवं उपलब्धता की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

बारकोड प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता उत्पाद की वास्तविक जानकारी भी जांच सकेंगे।प्रशासन का मानना है कि इस पहल से शराब विक्रय प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को सही एवं स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। साथ ही दुकानदारों द्वारा मनमानी अधिक कीमत वसूलने या गलत जानकारी देने जैसी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी।आबकारी विभाग ने सभी संबंधित दुकानदारों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है तथा उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी है।

जिला संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न

डिंडौरी। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न संगठनों द्वारा एजेंडा प्रस्तुत कर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई।मध्यप्रदेश शिक्षक संघ अजाक्स अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ सहित अन्य संगठनों ने संयुक्त रूप से बताया कि जिले में शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े कई प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रकरण लंबे समय से लंबित हैं।

बैठक में प्रमुख रूप से नियमित विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित करने समयमान वेतनमान आकस्मिक एवं अतिरिक्त कार्यों का भुगतान मानदेय तथा लंबित देयकों के शीघ्र भुगतान की मांग उठाई गई। इसके साथ ही अनुकंपा नियुक्ति पदोन्नति वरिष्ठता सूची एवं स्थानांतरण से संबंधित मामलों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षा शुल्क माफी और अन्य शासकीय लाभ समय पर उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई। दैनिक वेतनभोगी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण और सेवा शर्तों में सुधार का मुद्दा भी उठाया गया।कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया को अवगत कराया गया कि इन विषयों को आगामी बैठक में शामिल कर विभागीय समन्वय के साथ निर्णय लिया जाए जिससे कर्मचारियों को समयबद्ध राहत मिल सके। कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि लंबित फिक्सेशन सहित कर्मचारियों से संबंधित सभी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए।बैठक में सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आतिशबाजी और बैंड-बाजे के साथ निकला विजय जुलूस

शहपुरा में भाजपा की जीत का भव्य जश्न

शहपुरा। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद डिंडोरी जिले के शाहपुरा नगर में उत्सव का माहौल छा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साह और उमंग के साथ विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया।जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और बैंड-बाजों के साथ पूरे नगर में रैली निकाली। ढोल-नगाड़ों की धुन और पार्टी के जयघोष से पूरा शहर गूंज उठा। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और इसे जनता के विश्वास की जीत बताया।

कार्यक्रम में शाहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह जीत पार्टी की नीतियों, मजबूत नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है।विजय जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होकर निकला, जहां जगह-जगह लोगों के बीच मिठाई वितरित कर खुशी साझा की गई। इस दौरान पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।कार्यक्रम में भाजपा शाहपुरा मंडल और मानिकपुर मंडल के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में इस जीत को विकास, सुशासन और राष्ट्रहित की विजय बताया।

कलेक्टर ने खुद ट्रक चलाकर किया जनगणना रथ का शंखनाद

सटीक जानकारी ही विकास का आधार: डॉ. केदार सिंह

शहडोल।

जिले में जनगणना 2026 के महाभियान की भव्य शुरुआत हुई। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जागरूकता के लिए तैयार किए गए विशालकाय जनगणना रथ को हरी झंडी दिखाने के साथ-साथ खुद स्टीयरिंग संभालकर उसे चलाया। उन्होंने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे गणना कार्य में लगे कर्मचारियों का सहयोग करें और अपनी सही जानकारी दर्ज कराकर देश की प्रगति में भागीदार बनें।

जब कलेक्टर बने रथ के सारथी

शहडोल जिला प्रशासन ने जनगणना के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के लिए एक अभिनव पहल की है। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उस वक्त हर कोई हैरान रह गया, जब कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने केवल औपचारिकता के लिए हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि वे खुद एक चालक (ड्राइवर) की भूमिका में नजर आए। उन्होंने विशालकाय ट्रक, जिसे एक आधुनिक जनगणना रथ के रूप में परिवर्तित किया गया है, की केबिन में चढ़कर इंजन स्टार्ट किया और उसे कलेक्ट्रेट परिसर से मुख्य मार्ग तक चलाकर ले गए। इस दौरान कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने अपने बयान में कहा जनगणना राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। मैं खुद इस गाड़ी को चलाकर यह संदेश देना चाहता हूँ कि शासन का प्रत्येक स्तर इस कार्य के लिए समर्पित है। हमारा उद्देश्य है कि जिले का एक भी व्यक्ति इस गणना से न छूटे। उन्होंने आगे कहा कि रथ के माध्यम से हम डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे ताकि वे जनगणना के महत्व को समझ सकें।

डिजिटल जनगणना और रथ की विशेषताएं

यह जागरूकता रथ आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें एक विशालकाय एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर जनगणना के विभिन्न चरणों, पूछे जाने वाले प्रश्नों और इसके लाभों से संबंधित वीडियो दिखाए जाएंगे। यह रथ जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी वार्डों में भ्रमण करेगा। अभियान की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कलेक्टर ने दूसरा महत्वपूर्ण बयान दिया, इस बार की जनगणना डिजिटल स्वरूप में है। 1 मई से शुरू होने वाली प्रारंभिक प्रक्रियाओं के बाद, विभिन्न चरणों में मकानों का सूचीकरण और फिर जनसंख्या की गिनती की जाएगी। जनता को यह समझना होगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही अगले 10 वर्षों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की योजनाएं तैयार की जाएंगी।

गणना कर्मचारियों का करें सहयोग

जनगणना अभियान को सफल बनाने के लिए हजारों प्रगणकों (कर्मचारियों) की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर ने विशेष रूप से कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके स्वागत पर जोर दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में तीसरी बार दोहराया जब गणना दल आपके घर आए, तो उन्हें अपना मित्र समझें। उनसे कोई भी जानकारी न छुपाएं। आपकी गोपनीयता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी सत्यता जिले के विकास के लिए अनिवार्य है। कर्मचारियों को सहयोग देना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है।

भारत सरकार और मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह अभियान विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहाँ साक्षरता या जागरूकता की कमी है। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना के डेटा का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, अतः किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने अपने चौथे और अंतिम बयान में जिलेवासियों को प्रेरित करते हुए कहा शहडोल को विकास की दौड़ में अग्रणी रखने के लिए हमें अपनी संख्या और अपनी जरूरतों का सही डेटा सरकार तक पहुँचाना होगा। आइए, इस जनगणना रथ का स्वागत करें और एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें। कलेक्टर के इस अनूठे प्रयास और स्वयं ट्रक चलाकर अभियान की शुरुआत करने की चर्चा पूरे संभाग में हो रही है। यह रथ अब जिले के हर कोने में जाकर सरकार के विकास के संकल्प को घर-घर पहुंचाएगा।

हरिभूमि

नर्मदा भूमि

10

जबलपुर, मंगलवार 5 मई 2026

login : www.haribhoomi.com

करेली | तेंदूखेड़ा | श्रीधाम | सालीचौका | सुआतला | गाडरवारा | राजमार्ग | साईंखेड़ा | चीचली | करकबेल

खबर संक्षेप

दीवान शैलेन्द्र सिंह जिला संगठन प्रभारी बनें

तेंदूखेड़ा। इन दिनों म प्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी संगठन में मजबूती लाने की दिशा में ब्लाक और जिला स्तर पर नित नई व्यवस्थाओं में सक्रिय बनें हुए हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रहे कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव दीवान शैलेन्द्र सिंह को नरसिंहपुर जिले का संगठन महासचिव का दायित्व सौंपा गया है। उनके इस मनोनयन पर कांग्रेस कार्य कर्ताओं ने बधाईयां प्रेषित की हैं। तथा संगठन को मजबूती मिलेगी ऐसी अपेक्षा व्यक्त की गई है। गौरतलब रहे कि दीवान शैलेन्द्र सिंह पूर्व में म प्र शासन के मंत्री रहे स्व दीवान चंद्रभान सिंह के सुपुत्र हैं एवं कांग्रेस की हर गतिविधि में सक्रिय बनें हुए हैं।

दक्षता प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन आज से

हरिभूमि न्यूज- नरसिंहपुर। सरस्वती शिशु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर में 5 मई से 20 मई 2026 तक प्रांतीय शिशु वाटिका सामान्य दक्षता प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जा रहा है उद्घाटन सत्र में विद्या भारती अखिल भारतीय मार्गदर्शक अवनीश भटनागर, प्रांत एवं क्षेत्र शिशु वाटिका संयोजक प्रभात सिंह, प्रांत प्रमुख हरिराम तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष पंडित नीरज दुबे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं समाजसेवी महंत पीतमपुरी, व्यवस्थापक धर्मेंद्र सिंह ममार, गणमान्य नागरिकों की गरिमामय उपस्थिति मे किया जावेगा।

जल संरक्षण को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित

हरिभूमि न्यूज- नरसिंहपुर। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में म.प्र. साइंस एवं तकनीकी परिषद भोपाल के सहयोग से जल संरक्षण विषय पर छात्र-छात्राओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.बी. सिंह के मार्गदर्शन में विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जल संवर्धन और प्रबंधन पर एक दिवसीय सेमिनार के साथ-साथ पेंटिंग एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आयोजित प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चित्रकला प्रतियोगिता में मानस गुप्ता ने प्रथम, पूजा चैधरी ने द्वितीय और सोनम जाटव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जिन्हें नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में पलक कहार और कृष्णा साहू ने बाजी मारी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में देवानंद धानक (सहायक प्राध्यापक, तेंदूखेड़ा) और कौशल तिवारी (बरमान कॉलेज) उपस्थित रहे। वक्ताओं ने नरसिंहपुर जिले में जल आधारित समस्याओं और चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए भूजल संग्रहण की वैज्ञानिक पद्धतियों को समझाया। उन्होंने विशेष रूप से कृषि के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन और धान, गन्ना एवं गेहूं जैसी फसलों में जल प्रबंधन के महत्व पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं। साथ ही मध्यप्रदेश शासन के जल गंगा अभियान के सकारात्मक प्रभावों से भी छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया। कार्यक्रम के अंत में छात्रा कृष्णा साहू ने आभार व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में वनस्पति विभागाध्यक्ष श्रीमती शोभा मिश्रा सहित महाविद्यालय के समस्त स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

जांच में नहीं मिला डायवर्सन का आदेश, कृषि भूमि पर किया जा रहा खनन

पांजरा खदान को लेकर बढ़ रहा संदेह

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

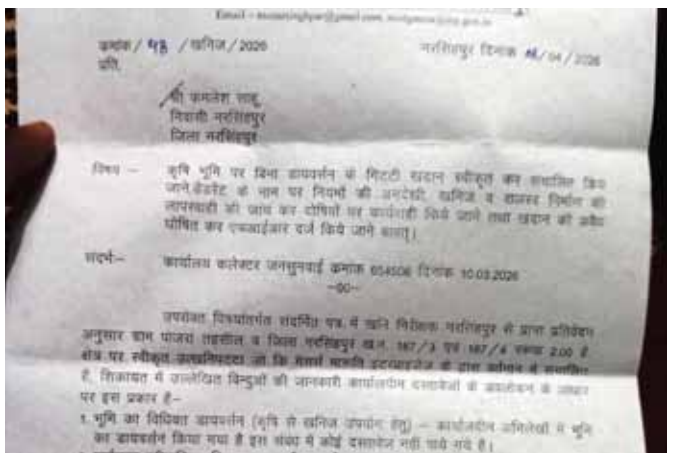

सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड़ों के तहत उत्खनन करने व अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग बनाया गया है जिससे जिले मे होने वाले अवैध खनन को रोका जा सके। लेकिन अवैध करोबारी प्रशासन की आंखो पर धूल झोंकने का भी भरसक प्रयास करते है और सरकार से राजस्व चुराकर अपना करोबार चलाने मे सफल होने के लिए प्रयासरत रहते है। ऐसा ही मामला जिले की ग्राम पांजरा में संचालित एक गिट्टी खदान का सामने आया। उक्त मामले में प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी संदेह बढ़ा दिया। हाल ही में सामने आए दो अलग-अलग समय के सरकारी दस्तावेजों ने खनन पट्टे की वैधता को लेकर ऐसा विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। जिससे विभागीय कार्यप्रणाली भी संदेह बढ़ रहा है। हालाकि उक्त मामले को लेकर कोई वैधानिक कार्रवाई नही की गई है। वहीं संदेह है कि नियमों को ताक पर रखकर रसूखदारों को प्रशासनिक संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे राजस्व को भारी क्षति पहुँचने की संभावना है।

अभिलेखों में डायवर्जन का नहीं उल्लेख

कलेक्टर कार्यालय की खनिज शाखा द्वारा 8 अप्रैल 2026 को जारी पत्र क्रमांक 48 में एक चैंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस जाँच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि कार्यालयीन अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर उक्त भूमि का कृषि से खनिज उपयोग हेतु कोई भी विधिवत डायवर्जन दस्तावेज नहीं पाया गया है। नियमानुसार किसी भी कृषि भूमि पर उत्खनन कार्य शुरू करने से पहले उसका विधिक डायवर्जन अनिवार्य है। इसके बावजूद प्रशासन ने इस कमी को जानते हुए भी खदान के संचालन को रोकने के बजाय उसे केवल कागजों पर दर्ज करना उचित समझा है। अब देखना होगा प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है वही जानकारों द्वारा बताया जा रहा है कि उत्खनी पट्टे के लिए डायवर्सन की आवश्यकता नही होती है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है।

जांच मे यह आया सामने

उक्त खदान को लेकर की जांच पड़ताल में प्रशासन द्वारा बताया गया कि खदान के पास पर्यावरण स्वीकृति 10 वर्ष के लिए है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति 2029 तक वैध है। यहाँ बड़ा सवाल यह उठता है कि जब भूमि का मूलभूत कानूनी स्वरूप (डायवर्सन) ही स्पष्ट नहीं था, तो पर्यावरण और प्रदूषण विभाग ने अपनी एनओसी किस आधार पर जारी कर दी। हालांकि उक्त संबंध में खदान को लेकर लोगों द्वारा अनेकों चर्चा की जा रही है वही खनिज विभाग की कार्यप्रणाली पर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि खदान के संबंध मे प्राप्त अन्य दस्तावेजों मे भी भिन्नता है जिसे लेकर कोई ठोस जानकारी प्रशासन द्वारा नही दी गई। प्रशासन को चाहिए की खदान का भौतिक सत्यापन कर दस्तावेजों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए।

जांच कर ठोस कार्रवाई कर प्रशासन

उक्त खदान को लेकर वर्ष 2023 में ही इस खदान के पट्टे की प्रक्रिया मेसर्स मारुति इंटरप्राइजेज के पक्ष में पूरी कर ली गई थी। 14 मार्च 2023 को जारी पत्र के अनुसार, ग्राम पांजरा के खसरा नंबर 187/3 और 187/4 के 2.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर 10 साल के लिए पट्टा स्वीकृत किया गया था। उस समय अनुबंधित शर्तों में सीमांकन और अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लेख था, लेकिन 2026 की जाँच रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि तीन साल बीत जाने के बाद भी डायवर्जन जैसा अनिवार्य कार्य कागजों में नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता द्वारा खदान को अवैध घोषित कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की चाल अब भी सुस्त बनी हुई है। हालाँकि पत्र में दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन मौके पर खदान का संचालन बंद करने या भारी जुर्माना लगाने जैसे ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय जनचर्चा है कि यदि इस मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो यह आने वाले समय में जिले का सबसे बड़ा खनन घोटाला साबित हो सकता है। अब जनता की नजरें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि वह पारदर्शिता अपनाता है या फाइल को ठंडे बस्ते में डाल देता है।

इनका कहना है

उक्त मामले को लेकर बताया गया कि उत्खनि पट्टे के लिए डायवर्सन की आवश्यकता नही होती है शेष स्वीकृति खदान संचालक के पास है एवं शासकीय रायल्टी काटी जा रही है।

ओ पी बद्येल,
खनिज अधिकारी

सूने घर में चोरी, बच्चों की गुल्लक भी ले उड़े चोर

हरिभूमि न्यूज- नरसिंहपुर। केंद्रीय जेल परिसर में स्थित एक जेल प्रहरी के सूने सरकारी क्वार्टर में रविवार रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में घुसकर मासूम बच्चों की गुल्लक तोड़ दी और उसमें रखी जमा पूंजी लेकर फरार हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जेल प्रहरी विजय प्रजापति अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने गोटेगांव गए हुए थे। इस दौरान चोर तारवाड़ी लांघकर परिसर में दाखिल हुए और मुख्य गेट का ताला कुंदे सहित उखाड़ दिया। अंदर घुसकर बदमाशों ने अलमारी और गोदरेज के लॉकर तोड़कर कीमती सामान की तलाश की। जब उन्हें कोई बड़ी नकदी हाथ नहीं लगी, तो उन्होंने विजय प्रजापति की साढ़े छह साल की बेटी आराध्या और छह माह के बेटे गोपाल की स्टील की गुल्लक को अपना निशाना बनाया। इन गुल्लकों में रखे पैसे, चांदी की हाय-चंद्रमा और एक चांदी की अंगूठी लेकर चोर रफूचक्कर हो गए। सोमवार सुबह जब परिवार वापस लौटा, तो घर का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू की। जेल प्रहरी विजय प्रजापति ने बताया कि यद्यपि कोई बड़ी चोरी नहीं हुई है, लेकिन बच्चों की मेहनत से जमा की गई गुल्लक टूटने से परिवार आहत है। पुलिस ने फरियादी को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी है और मामले की जांच की जा रही है।

नगर के गौरव की सटोरिया पर विशेष कृपा, पुलिस चौकी से सौ मीटर दूर चल रहा सट्टे का खेल

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्पूर्ण जिले मे अच्छी पुलिस व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे है लेकिन विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पुलिस अधीक्षक के प्रयासों पर पानी फेरने का काम करते नजर आ रहे है। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय में सामने आया जहां पर कोतवाली पुलिस द्वारा बनाई गई चैकी से महज सौ मीटर दूर सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। सटोरिए के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का उसे कोई डर भय नहीं है। जिससे प्रतीत होता है कि सटोरिए पर कोतवाली पुलिस की विशेष कृपा है। लोग अपना घर व जेवर बेचकर भी सट्टा खेल लेते है और परिवार उनकी कारगुजारी का दंश झेलता है वही जिला मुख्यालय मे भी सट्टे का कारोबार चर्म सीमा पर जारी है पुलिस द्वारा देखकर अनदेखी की जा रही है। जिला मुख्यालय मे चल रहे सट्टे के स्थान की दूरी कोतवाली थाने से महज 1 किलो मीटर ही होगी लेकिन पुलिस के हाथ सटोरियों तक नहीं पहुंच पा रहे है। वही सटोरिया के अड्डे से तकरीबन 100 मीटर दूर गांधी चैक पर पुलिस की सहायता चैंकी भी बनी हुई जो शहर के हावो हवा व अपराधों को नियंत्रण के उद्देश्य से बनाई गई वही चैकी पर बैठने वाले पुलिस कर्मियों द्वारा आज तक उक्त सटोरियों पर कोई कार्रवाई नही की गई जो मिलीभगत होने की आशंका को दर्शा रही है। जिला मुख्यालय के गांधी चैंक क्षेत्र मे पुल के पास के क्षेत्र मे धड़ल्ले से सट्टा खिलाया जा रहा है। सटोरियों के नेटवर्क इतने मजबूत होते है कि पुलिस के आने की सूचना उन्हे पहले ही लग जाती है और वह अपनी दुकान बंद कर भाग जाते है और पुलिस के हाथ खाली के खाली रह जाते है। वही पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अनेको प्रयास किये जा रहे है। परन्तु अपराधों पर कमी नजर नहीं आ रही है। जो पुलिस की असफलता को दर्शा रही है। सट्टे के गंदे खेल मे की युवा पीढ़ी भी शामिल होती जा रही है जो लोगो के लिये चिंता जनक है। युवाओं को 1 के 80 के चक्कर का मायाजाल से इस तरह भ्रमित किया जा रहा है कि वह इस खेल मे आसानी शामिल हो रहे है और परिणाम यह होता है कि अपना घर जेवर बेचकर सट्टे का कर्ज चुकाते रहते है। लोगो को इस बात की चिंता अधिक होने क लगी है कि समाज का ये गंदा खेल कब बंद होगा। सटोरिए पर पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करना ऐसा दर्शा रहा है कि सटोरिया कोतवाली पुलिस के गौरव को बढ़ा रहा है। लोगो द्वारा कहा जा रहा है दीपक के गौरव से प्रकाशमान हो रहा सट्टे का कारोबार और इसे बंद कराने मे पुलिस असफल नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सटोरिये आखिर कब तक पुलिस से बच पाते है या पुलिस ऐसे ही असफल बनी रहेगी। उक्त मामले से ऐसा प्रतीत होता है कि सटोरिया पर नगर के गौरव की विशेष कृपा है।

सूखने लगीं बारांझ और पाणाझिर नदियां

तेंदूखेड़ा

जल संरक्षण और पानी बचाओ जल स्त्रोतों के उचित रखरखाव को लेकर शासन प्रशासन बड़े बड़े दावे और घोषणाएं करती हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। उपेक्षा के चलते उचित रखरखाव के अभाव में क्षेत्र की जीवनदायनी मानी जाने वाली बारांझ और पाणाझिर नदियां गर्मी की शुरुआत में ही पूरी तरह सूख चुकी हैं। इन नदियों का अस्तित्व अब विलुप्ति की कगार पर है। जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर होने की स्थिति में है और बेजुबान मवेशियों के सामने पानी का संकट खड़ा हो गया है।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी देखी हकीकत

हैरानी की बात यह है कि तेंदूखेड़ा-बरमान मुख्य मार्ग पर स्थित इन नदियों के ऊपर से प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला गुजरता है। फिर भी इन नदियों के पुनरुद्धार के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाया। बारिश के कुछ समय बाद ही नदियां सूख जाती हैं। जो क्षेत्र के गिरते भू जल स्तर और प्रशासनिक उदासीनता का प्रमाण है।

नक्कारखाने में तूती की आवाज बन गई स्टॉप डैम की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन दोनों नदियों पर स्टॉप डैम का निर्माण करा दिया जाता तो न केवल क्षेत्र के हजारों मवेशियों की प्यास बुझेगी साथ ही साथ सिंचाई की सुविधा मिलने से हजारों हेक्टेयर भूमि फिर से लहलहा उठेगी। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान पूर्व विधायक संजय शर्मा ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और स्वीकृति की उम्मीद भी जगी थी लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह योजना सरकारी फाइलों में दबकर रह गई।

जर्जर पुल दे रहे बड़े हादसे को आमंत्रण

नदियों के साथ साथ इन पर बने पुलों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो चुकी है। पुलों की ऊंचाई कम होने के कारण सामान्य बारिश में भी ये जलमग्न हो जाते हैं। उचित मरम्मत न होने से पुलों के नीचे की मिट्टी का कटाव होता चला जा रहा है।जिससे अब वाहनों के गुजरने पर इनमें कंपन महसूस होता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि मानसून के पूर्व पुलों का कायाकल्प और मरम्मत नहीं की गई। तो आगामी बरसात में गंभीर हादसा हो सकता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि प्राचीन समय से ये नदियां कई गांवों का आधार रही हैं, लेकिन आज ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं शासन प्रशासन को जल्द ही स्टॉप डैम और पुल निर्माण पर ध्यान देना चाहिए ताकि क्षेत्र की हरियाली और पशुधन को बचाया जा सके।

कांग्रेस जनों ने क्रूज हादसे के दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। जबलपुर के बरगी बांध में हुए दुखद क्रूज हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस हृदय विदारक घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में नरसिंहपुर शहर कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने शहर के प्रमुख स्थल पर एकत्रित होकर कैंडल जलाए और मौन रखकर मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं। श्रद्धांजलि सभा में बॉबी खान, अस्सु नेमा, देवेन्द्र शुक्ला, अजय दुबे, अजय मालवीय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष रोहित पटैल, जनपद अध्यक्ष शैलेन्द्र राजपूत, अतुल चैरसिया, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष विवेक पटेल, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ईशान राय, बबलू कहार, अंकुर बटरी और शिवम पाठक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने ली समय सीमा की बैठक

हरिभूमि न्यूज - नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित कर विभागीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिए गए लक्ष्यों की पूर्ति समय-सीमा में करें। निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने के लिए, निर्माण कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग करें। आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने आयोजित बैठक में जल संचय जनभागीदारी 2.0 के अंतर्गत वन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, जन अभियान परिषद, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, शहरी क्षेत्र एवं जल संसाधन विभाग के कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने खेत-तालाब निर्माण, कंटूर ट्रेंच, वॉटर हार्वेस्टिंग के निर्माण कार्य तथा जल स्त्रोतों में नदी-नालों, तालाबों और बाबड़ियों इत्यादि की साफ-सफाई करने के निर्देश दिए।

अवैध वेंडर बेखौफ होकर कर रहे व्यापार, ट्रेन रुकने के पूर्व ही ट्रेन में सवार हो जाते हैं वेंडर

गंभीर दुर्घटना का अंदेशा कभी भी हो सकती हैं दुर्घटना आखिर जिम्मेदार कौन ठेकेदार या जांच अधिकारी श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडरों की भरमार, स्वास्थ्य के लिए बन रहे खतरा

गोटेगांव।

क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर इन दिनों अवैध वेंडरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिना अनुमति खाद्य सामग्री बेच रहे इन वेंडरों के कारण यात्रियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडराने लगा है। रेलवे के नियमों को नजरअंदाज कर प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही है, जिससे आमजन के सामने स्वच्छ और सुरक्षित भोजन का संकट खड़ा हो गया है।रेलवे विभाग के नियमों के अनुसार ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर खाद्य सामग्री बेचने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाणित होना अनिवार्य होता है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही ऐसे कर्मचारियों को रेलवे द्वारा अधिकृत फूड वेंडर कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि खाद्य सामग्री बेचने वाला व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है और उसे किसी भी प्रकार की संक्रामक बीमारी नहीं है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराया जा सके।लेकिन श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। यहां कई लोग बिना किसी अनुमति और स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के प्लेटफॉर्म तथा ट्रेनों में चाय, नाश्ता और अन्य खाद्य सामग्री बेचते नजर आते हैं। इन वेंडरों के पास न तो रेलवे का अधिकृत पहचान पत्र होता है और न ही स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रमाणपत्र। ऐसे में यात्रियों को मिलने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।यात्रियों का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में अवैध वेंडर घूमते रहते हैं, जो ट्रेनों में चढ़कर भी सामान बेचते हैं। कई बार ये लोग खुले में रखी खाद्य सामग्री बेचते हैं, जिससे संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है। गर्मी के मौसम में यह खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि खराब या दूषित खाद्य पदार्थ यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं।स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि स्टेशन परिसर में अवैध वेंडरों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। साथ ही केवल उन्हीं वेंडरों को खाद्य सामग्री बेचने की अनुमति दी जाए जिनके पास रेलवे द्वारा जारी अधिकृत कार्ड और स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाणपत्र हो।यदि रेलवे प्रशासन समय रहते इस दिशा में कार्रवाई नहीं करता है तो यह समस्या यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छ भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करना रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।